आमोखस व मिडिया की खबरों व प्रथम समाचार पत्र

RNI No. UPHIN/2012/47484

जननायक समाट

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों अलीगढ़ हाथरस ऐटा कासगंज बदायूं बुलंदशहर मथुरा आदि से प्रसारित व अलीगढ़ से प्रकाशित

बर्ष :13 अंक :515 पृष्ठ –4 दिनांक 27 जून 2025 दिन शुक्रवार

यूपी में मानसून का अलर्ट! इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश की बौछारें पड़ रही हैं, कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश तो हो रही है. लेकिन, नोएडा–गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अब भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है. मौसम विभाग के अनुमान के बावजूद हल्की–फुल्की ही बारिश होकर रह जाती है. लोग अभी भी झमाझम बारिश की आस लगाए बैठे हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब पश्चिमी यूपी की ओर भी बढ़ गया है, जिसके बाद ये पूरे प्रदेश में छा जाएगा. 30 जून तक प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग ने आज 26 जून को भी पश्चिमी यूपी के अनेक स्थानों पर गरज–चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई हैं. पूर्वी यूपी में भी कई जगहों पर बारिश होगी. आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला तेज होगा. 29 जून से पूर्वी यूपी के लगभग सभी स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान कहीं–कहीं मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली की चमक की भी संभावना जताई है. हालांकि,

अगले पांच दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा. यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर में अनेक जगहों पर बा. रिश होगी. इस दौरान कुछ जगहों पर बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का भी यलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं ललितपुर, मीरजापुर, सोनभद्र और चंदौली में भी अनेक जगहों पर बारिश होने का अनुमान है. नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, संभल, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, कासगंज, एटा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर में कुछ जगहों पर आज बारिश होगी, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में एक या दो जगहों पर बा. रिश का अनुमान है.

लखनऊ पति की मौत के ढाई माह बाद पत्नी ने गोमती में कूदकर दी जान, जानें पूरा मामला

लखनऊ हजरतगंज के सिकंदर नगर नई बस्ती में रहने वाली कविता निषाद (30) ने बुधवार को लक्ष्मण मेला के पास गोमती नदी में कूदकर जान दे दी। कविता के पति महेश ने 2 अप्रैल को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।मामले में कविता ने हजरतगंज कोतवाली में अलीगंज निवासी रिटायर्ड जज अनिल कुमार श्रीवास्तव और उनकी पत्नी वंदना के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। परिजन का आरोप है कि उक्त मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से कविता आहत थी और इसी वजह से उसने जान दी।भाई अंशु ने बताया कि बहनोई महेश की आत्महत्या के कुछ दिन बाद उनकी बहन कविता सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अर्जुनगंज अहिमामऊ में अपने दूसरे मकान में बच्चों माधव और शुभी के साथ रह रही थी। कविता ने मकान का एक हिस्सा किराए पर दिया था। उसी रुपये से घर का खर्च चल रहा था। बुधवार सुबह कविता बच्चों संग भाई के घर सिकंदर नगर पहुंची थी। दोपहर करीब 1रू30 बजे कविता पुलिस चौकी पर दरोगा से मिलने की बात कह कर घर से निकली।इसके बाद लक्ष्मण मेला मैदान के पास गोमती नदी में कूद गईं। कविता को नदी में कूदता देखकर लोगों ने शोर मचाया। स्थानीय लोगों व परिजन ने कविता को नदी से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची। आनन–फानन में कविता को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाई अंशु का आरोप है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्यवाही की होती तो बहन कविता की जान नहीं जाती।आरोप है कि कविता पति की खुदकुशी मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर चौकी और कोतवाली का चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस टालमटोल करती रही। अंशु ने बताया कि बहनोई और अब बहन के जाने के बाद भांजी व भांजे की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। उन्होंने पुलिस से रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी के के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।अंशू ने बताया कि बहनोई महेश अलीगंज निवासी रिटायर्ड जज अनिल कुमार श्रीवास्तव के यहां खाना बनाते थे। 2 अप्रैल को महेश ने मोबाइल पर मालकिन को संबोधित करते हुए एक वीडियो बनाया था। जिसमें कहा था कि, मम्मी जी...अगर आपको लगता है कि सारा रुपया मैंने निकाला और बांट लिया, पर ऐसा नहीं है। मैंने रुपया नहीं निकाला है। यह राहुल की हरकत है।अमित भी यह बात जानता है। राहुल ने यह बात खुद बताई थी कि पिन खोलकर उसने पैसा निकाला था। मेरे पास डेढ़ लाख रुपये नहीं हैं जो आपको दे सकूं। इसलिए आज होशो हवास में सुसाइड करने जा रहे हैं। मम्मीजी जी आज के बाद नहीं मिलेंगे आप से, क्योंकि आज हम आत्महत्या करने जा रहे हैं।होली के समय रिटायर्ड जज के घर में साढ़े छह लाख रुपये की चोरी हुई थी। बहनोई महेश ने चोरी नहीं की थी। इसके बाद मालकिन वंदना महेश पर चोरी का आरोप मढ़ रही थी। 17 मार्च को उन्होंने अलीगंज थाने में पति के खिलाफ तहरीर दी थी। पति से पूछताछ के बाद पुलिस ने लिखापढ़ी करके छोड़ दिया था। इसके बाद से सेवानिवृत्त जज उनके बहनोई को धमका रहे थे कि डेढ़ लाख रुपये एक अप्रैल तक दे देना नहीं तो घर जब्त कर लिया जाएगा।

लखनऊ पुलिस वैन में सजायाफ्ता बंदी की पिटाई, तमाशबीन बनी पुलिस

लखनऊ, जेल से पेशी पर गए बंदियों की पुलिस वैन में मारपीट का बुधवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में हत्या के आरोप में सजायाफ्ता बंदी रफत खान साथियों के साथ दूसरे बंदी मोहम्मद फरदीन को पीट रहा है। करीब 27 सेकेण्ड में वीडियो में बंदी पर लात व थप्पड़ की बौछार की गयी।वैन में दूसरे बंदी और पुलिस भी मौजूद है, लेकिन किसी ने भी नहीं रोका। वीडियो में पीटते हुए दिख रहा बंदी तीन जून को जेल से जमानत पर बाहर आ चुका है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके जायसवाल का कहना है कि वायरल वीडियो 3 जून से पहले का है। मामले में वैन में मौजूद पुलिस, पिटने और पीटने वाले बंदियों में से किसी ने शिकायत नहीं की।बुधवार को वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि दबंग बंदी रफत खान दूसरे बंदी फरदीन को बुरी तरह पीट रहा है। पीटने में एक बंदी और शामिल हो जाता है। पिटाई से बंदी नीचे बैठ गया। जिसके बाद उसे थप्पड़ और लात से मारा गया। जेल अधीक्षक ने माना कि पेशी के लिए भेजी गई पुलिस वैन के अंदर ही मारपीट हुई।मारने वाला और पिटने वाले बंदी की पहचान की गई है। पीटने वाला बंदी काक. ोरी निवासी सजायाफ्ता रफत खान है और मार खाने वाला फरदीन है। सूत्रों की माने तो उक्त वीडियो वैन में मौजूद एक सिपाही ने ही बनाया था। गुरुवार को जेल प्रशासन इस मामले की जांच शुरू करेगा।

इटावा की घटना पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान– संविधान से भी पहले हमारा धर्म ग्रंथ

उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक से दुर्व्यवहार मामले पर जमकर सियासत की जा रही है. इस बीच सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर आसीन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है. ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने इस घटना की निंदा की और कहा हमारी परंपरा में भगवान से संवाद स्थापित करने के लिए ब्राह्मण अधिकृत हुआ है. इसलिए कथा उन्ही के द्वारा की जानी चाहिए. ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एबीपी से बात करते हुए कहा कि ये घटना बहुत निंदनीय है. व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कभी भी स्व. ीकार नहीं किया जा सकता. लेकिन, घटना के बाद जिस तरह से राजनीति हो रही है लग रहा है कि पहले से ही सोचा समझा मामला है. यह हमारे सनातन धर्म की क्षति है. इसीलिए राजनेताओं को धर्म के मामले में नहीं आना चाहिए.उन्होंने कहा कि वैसे हमारी परंपरा में तो काकभुशुण्डि (कौआ) ने भी कथा कही थी. राम कथा का ऐसा महात्म है. भगवत प्रेम में कथा हो रही हो तो कोई भी कथा कह सकता है. लेकिन, सकाम अनुष्ठान के लिए कथा ब्राह्मण द्वारा ही कही जाती है. जिस प्रकार न्यायालय में व्यक्ति अपना मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील को अधिकृत करता है. उसी तरह इस विषय में भी अधिकृत व्यक्ति के तौर पर ही कथा कही जाती है. उन्होंने कहा कि जैसे न्यायालय से संवाद करने के लिए वकील अधिकृत होता है उसी तरह हमारी परंपरा में भगवान से संवाद स्थापित करने के लिए ब्राह्मण अधिकृत हुआ है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सपा सांसद द्वारा मनुस्मृति को लेकर दिए बयान पर कहा कि हमारे धर्माचार्य संविधान की कथा कहने वाले को तो नहीं रोकते. वो संविधान की कथा कहे उन्हें कौन रोक रहा है. लेकिन, हमारे विषय को संविधान से क्यों जोड़ा जा रहा है. धर्म के विषय में उसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, संवैधानिक व्यक्ति नहीं. शकं. राचार्य ने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ से ऊपर संविधान नहीं हुआ, संविधान से भी पहले हमारा धर्म ग्रंथ रहा है. पूरे ब्रह्मांड में हमारा मनुस्मृति लागू है.

यूपी के किसानों और पशुपालकों के लिए खुशखबरी, आय बढ़ाने के लिए दुग्ध क्षेत्र में हुआ बड़ा समझौता

उत्तर प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने दुग्ध उद्योग को मजबूत बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है . मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. इसके तहत प्रदेश के चार बड़े डेयरी और पशु आहार प्लांट का संचालन अब एनडीडीबी के जिम्मे होगा. इस समझौते के तहत कानपुर गोरखपुर और कन्नौज में बने तीन डेयरी प्लांट और अंबेडकरनगर में स्थित पशु आहार निर्माणशाला को एनडीडीबी चलाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे डेयरी सेक्टर में क्रांतिकारी कदम बताया. उन्होंने कहा कि इन इकाइयों के संचालन से किसानों को बिना अतिरिक्त सरकारी खर्च के सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.सीएम योगी ने कहा कि दुग्ध क्षेत्र प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. अगर हम इसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से बढ़ाएं . तो यूपी देश ही नहीं दुनिया में भी अपनी पहचान बना सकता है . उन्होंने महिला डेयरी उत्पादकों की भागीदारी को भी सराहा और कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है. इस अवसर पर एनडीडीबी के चेयरमैन मीनेश शाह ने कहा कि यूपी के

ये प्लांट भविष्य में लाभकारी मॉडल के रूप में स्थापित किए जाएंगे. हम पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता के साथ काम करेंगे. कानपुर डेयरी प्लांट 160.84 करोड़ की लागत से बना है जो रोजाना 4 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग कर सकता है. गोरखपुर और कन्नौज में बने प्लांट 61.80 करोड़ और 88.05 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं जिनकी क्षमता 1–1 लाख लीटर प्रतिदिन है. अंबेडकरनगर की पशु आहार निर्माणशाला 18.44 करोड़ की लागत से बनी है जो 100 मीट्रिक टन पशु आहार रोज तैयार करती है. इन इकाइयों का संचालन पहले से तैयार था लेकिन खरीदार न मिलने और संचालन में कि. ठनाई के चलते पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे थे. अब एनडीडीबी के आने से इन इकाइयों को नई जान मिलेगी और किसानों को समय पर भुगतान गुणवत्ता वाले उत्पाद और बेहतर बाजार मिलेगा. गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है . लेकिन अब तक तकनीक और प्रबंधन की कमी के चलते किसानों को उनके दूध का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था. इस समझौते के बाद प्रदेश में दुग्ध उद्योग को मजबूती मिलेगी और पशुपालकों को नया सहारा मिलेगा. सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस मॉडल में सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और राजस्व का लाभ किसानों के साथ साझा किया जाएगा . इससे यह मॉडल पारदर्शिता और लाभ का उदाहरण बनेगा.

यूपी पुलिस में महिला सिपाही को वर्दी पहनकर रील बनाना पड़ा भारी, हुई विभागीय कार्यवाही

औरैया जनपद के अछल्दा थाने की महिला सिपाही पॉली भारद्वाज इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं हुईं हैं. उन्होंने वर्दी में थाने के अंदर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जो वायरल हो गया. वायरल होने के बाद अब महिला सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई है.आपको बताते चलें कि यूपी पुलिस विभाग ने ड्यूटी के दौरान रील बनाने पर पहले ही कठोर नियम बना रखे हैं. पुलिस विभाग की तरफ से जारी सख्त आदेश में साफ तौर पर पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है और इस तरह के कृत्य न करने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद इस महिला सिपाही के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया.पुलिस विभाग की तरफ से पुलिसक. र्मियों को नसीहत दी गई है और कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी वर्दी में रील बनाकर या परिसर के भीतर की गोपनियता आदि को सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं कर सकता है.अगर किसी भी अधिकारी या पुलिसकर्मी ने ऐसी हरकत की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसके बावजूद भी महिला पुलिसकर्मी के द्वारा सा. `शल मीडिया पर वीडियो डाली गईं हैं. यह वायरल पोस्ट जब अधिकारियों तक पहुंची तो तुरंत एक्शन लिया गया साथ ही महिला आरक्षी ने अपने एकाउंट से समस्त वीडियो भी डिलीट कर दिए हैं. इस वक्त महिला सिपाही के इंस्टाग्राम पर हैं 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद आला अफसरों ने खासी नाराजगी जताई है. वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी सदर अशोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला आरक्षी महिला थाने में तैनात है जिसके द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट की गई थी जिस संबंध में महिला आरक्षी ने समस्त पोस्ट को हटा दिया है.वायरल वीडियो में एक वीडियो महिला थाने पर नियुक्ति के समय की है जिसमे फरियादी महिला के साथ आए हुए बच्चे को दुलारते हुए है. तथा दूसरा वीडियो थाना अछल्दा में नियुक्ति के दौरान का है.जो कि एक वर्ष पुराना है.फिलहाल पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर के द्वारा महिला आरक्षी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या महिला आयोग सदस्य की आई प्रतिक्रिया, बोलीं- कुछ लोग ले चुके दानव का रूप

राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने हाथरस में महिला जन सुनवाई में कहा कि कुछ लोग दानव का रूप ले चुके हैं। ऐसे लोगों को यह भी नहीं दिखाई देता है कि यह छोटी बच्चियां हैं, इनके साथ हम क्या कर रहे हैं।जनपद फिरोजाबाद के एक गांव में हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग दानव का रूप ले चुके हैं। ऐसे लोगों को यह भी नहीं दिखाई देता है कि यह छोटी बच्चियां हैं, इनके साथ हम क्या कर रहे हैं।यह बातें उन्होंने 25 जून को तहसील सदर में महिला जन सुनवाई के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा रही है। छोटी बच्चियों को बहलाने–फुसलाने के मामले ज्यादा आ रहे हैं। इसे लेकर पुरुष वर्ग कहीं न कहीं जिम्मेदार है।उन्होंने कहा कि घरेलू विवाद बढ़ रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। महिलाओं को कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो भी महिलाएं उनके पास आई है, उनको न्याय दिलाया जा रहा है। दोनों पक्षों की सुनवाई की जा रही है। प्रयास यह है कि इन मामलों को समझौते से निपटाया जा सके।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई आज हाथरस कोर्ट से दोषमुक्त युवकों को कहा था गैंगरेप का आरोपी, 2024 में हुई थी याचिका

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के हा. थरस जिले में आज मानहानि मामले में सुनवाई होगी। इस दौरान उन पर चार्ज तय किया जा सकता है।राहुल के खिलाफ बूलगढ़ी गांव के एक युवक की ओर से 7 महीने पहले को मानहानि की याचिका दायर की गई थी। आरोप है कि नाबालिग से गैंगरेप के एक मामले में युवक को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया था। पर राहुल ने ट्विटर पोस्ट करते हुए युवक को गैंगरेप का आरोपी कहा था।12 दिसंबर 2024 को हाथरस के बूलगढ़ी गांव में गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी।अब तक कई डेट्स निकल चुकीं, गवाही तक दर्ज नहीं हाथरस कोर्ट के एसीजेएम दीपक नाथ सरस्वती की अदालत में यह मामला चल रहा है। 12 दिसंबर 2024 को दर्ज हुए इस मुकदमे में अब तक सुनवाई की कई डेट्स निकल चुकी हैं। पर सुनवाई नहीं हुई। कभी वादी–प्रतिवादी पक्ष के वकील नहीं रहे तो कभी शिकायतकर्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। अब तक मामले में गवाहों की गवाही तक नहीं दर्ज हो सकी है। हालांकि परिवादी रामकुमार के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं। मामले में पिछली सुनवाई की तिथि 26 मई थी।हा. थरस के बूलगढ़ी गांव निवासी शिकायतकर्ता रामकुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव का दौरा किया और इसके बाद अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने 2 मार्च 2023 को कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए गए युवकों को दोबारा गैंगरेप आरोपी बताया। जबकि कोर्ट ने इन युवकों को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।राहुल गांधी को भेजा था नोटिस परिवादी ने पहले राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस भेजा था। लेकिन जवाब नहीं मिलने पर अदालत में परिवाद दाखिल किया गया।ष्मुकदमा जीतने के बाद मिली इज्जत, राहुल ने फिर छीनीष् परिवादी का कहना है कि कोर्ट से बरी होने के बाद वह सामान्य जीवन जी रहे थे, समाज में खोया सम्मान उन्हें मिल चुका था। लेकिन राहुल गांधी की पोस्ट ने उनकी प्रतिष्ठा को फिर से नुकसान पहुंचाया। उनका यह भी दावा है कि यह पोस्ट देश–विदेश में वायरल हुई और उन्हें दोबारा आपराधिक नजरिए से देखा जाने लगा।ष्राजनीति और जातिगत विद्वेष से प्रेरितष् परिवादी के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर का कहना था कि राहुल गांधी की पोस्ट राजनीतिक लाभ और जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए की गई। यह मामला एक मृत मुद्दे को जानबूझकर पुनर्जीवित कर अपमान करने का है।आजमगढ़ में रा. जभर बोले– मुसलमान सपा के गुलामरूअखिलेश साइकिल मुसलमान को दें, खुद कैरियर पर बैठें, तब पता चलेगा कितना दर्द होता है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में कहा– मु. सलमान सपा के गुलाम हैं। ये लोग हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, अमन–चौन की बात नहीं करते, बल्कि नफरत की बात करते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस नफरत सिखाने का काम करती हैं।

हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सुमरतगढ़ी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी

हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सुमरतगढ़ी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका की पहचान 24 वर्षीय पूनम के रूप में हुई है। पूनम की शादी सूरज के साथ 5 साल पहले हुई थी। सूरज सिलाई का काम करता है। पूनम दो बच्चों की मां थी।वह दो दिन पहले ही अपने मायके बैरिया, थाना हाथरस जंक्शन से लौटी थी। सुबह परिवार के लोगों ने पूनम का शव फांसी के फंदे पर लटका देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वहां पूछताछ और छानबीन की।पुलिस कर रही मामले को लेकर जांच पड़ताल... मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मायके पक्ष के लोगों ने कहा कि वे अभी यह नहीं बता सकते कि पूनम ने आत्महत्या क्यों की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हाथरस में हथकरघा कारोबार खत्म होने की कगार पर, नहीं मिल रहा प्रोत्साहन, पहले थीं 250 यूनिटें, अब हैं 20

करीब 20 साल पहले तक हाथरस जनपद के हथकरघा कारोबार में पॉवरलूम का रूप ले लिया, लेकिन यह पॉवरलूम में भी काफी पुरानी मशीनों से काम किया जा रहा है। यहां के कारोबारियों को प्रोत्साहन न मिलने के कारण कारोबार मानों खत्म होता जा रहा है। इस कारोबार को फिर एक पहचान के लिए कारोबारी किसी संजीवनी का इंतजार कर रहे हैं।हथकरघा उद्योग में हा. थरस की अपनी अलग पहचान थी। 1970 के दशक में जनपद में कई कॉटन मिल थीं, जिसमें हजारों श्रमिक कार्यरत थे, लेकिन धीरे–धीरे सभी मिलें बंद हो गईं। दो दशक पहले तक जिले में करीब 250 बड़ी यूनिटें थीं, जो हैंडलूम के साथ पॉवरलूम का कार्य करती थीं, लेकिन वर्तमान में लगभग 20 यूनिटों में ही इसका काम हो रहा है। इन यूनिटों को अब प्रोत्. साहन की दरकार है, क्योंकि इनकी मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं, जो कुछ चुनिंदा उत्पाद ही बना सकती हैं।हम पुरानी मशीनों से कारोबार कर रहे हैं। मुख्य रूप से धागे व कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं। हमें अभी तक कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, जिससे हम अपने कारोबार को और अधिक बढ़ा सकें।–वेंकटेश अग्रवाल, कारोबारी. ।इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में हाथरस की अलग पहचान थी, लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है। जब तक सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेगी, तब तक कुछ नहीं होगा।–अरविंद अग्रवाल, कारोबारी।छोटे स्तर पर कुछ लाभ सरकार से मिले हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, जिससे हम अपनी यूनिटों को आधुनिक रूप दे सकें। हम अपने उत्पादों को पानीपत के उत्पादों के साथ बेच रहे हैं।–बुद्धसेन माहौर, कारोबारी।आज भी हा. थरस में हजारों की संख्या में हथकरघा कारोबारी मौजूद हैं। इतना हुनर है कि कारोबार चमक सकता है, लेकिन यह सरकार की मंशा के बगैर नहीं हो सकता। क्योंकि मुकाबला पानीपत से है।–प्रकाश चंद्र, कारोबारी।पानीपत के उत्पादों के साथ मिलते हैं आर्डर हाथरस के पॉवरलूम कारोबार के उत्पाद की अलग पहचान है, लेकिन आधुनिक समय में अब बाजार में तमाम ऐसे उत्पाद हैं, जिनका उत्पादन यहां मुमकिन नहीं है। ऐसे में यहां के कारोबारी अपने उत्पादों को बेचने के लिए पानीपत से आधुनिक उत्पादों को मंगाकर उनकी आपूर्ति करते हैं।दूरदराज के प्रदेशों में होती है आपूर्ति हाथरस के पॉवरलूम में बनने वाले उत्पादों की आपूर्ति सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूरदराज के प्रदेशों में भी की जाती है। इसमें गुजरात के साथ राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तराखंड शामिल हैं।गलीचों की होती है विदेशों तक आपूर्ति हाथरस की दो बड़ी यूनिटों में पॉवरलूम के जरिए गलीचे यानी कॉरपेट तैयार होते हैं। यहां तैयार होने वाले कॉरपेट दिल्ली की बड़ी फर्में खरीदती हैं और उन्हें कई अन्य देशों में बेचती हैं। इस तरह के महंगे उत्पाद बनाने वाली यूनिटें अब काफी कम हैं।अधिकांश यूनिटें धागे व कपड़े बना रहीं हाथरस की अधिक. ांश यूनिटों में धागा और कपड़ा बन रहा है। इसमें सर्दियों में ओढ़ने वाले खेस यानी मोटे धागे से बनने वाली चादरें व अन्य उत्पाद शामिल हैं।कारोबार एक नजर मेंचार नामी मिलें थीं 1970 के दशक में 12 हजार से अधिक लोग करते थे काम20 बड़ी यूनिट ही अब मौजूद हैं जनपद में 02 हजार के करीब लोग करते हैं कामकाज60 करोड़ रुपये का सालाना का टर्नओवर 20 साल पहले तक छोटी बड़ी 250 यूनिटें थींप्रोत्साहन न मिलने से 20 यूनिट ही हैं संचालित

राज्य महिला आयोग सदस्य ने की जनसुनवाई स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी मिली, मरीजों को मास्क नहीं जताई नाराजगी

हाथरस के सासनी तहसील में राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने जनसुनवाई की। उन्होंने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनीं। कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया।अन्य मामलों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर एसडीएम सनी नीरज शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने सासनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। केंद्र में गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। प्रभारी चिकित्सक को साफ–सफाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने मरीजों से भी बा. तचीत की और उनका हाल–चाल पूछा।म. रीजों को पर्याप्त उपचार दिया जाए आयोग सदस्य ने स्वास्थ्य केंद्र की लैब का निरीक्षण किया और खुद अपनी शुगर की जांच करवाई। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को मास्क न मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याएं दूर की जाएं। साथ ही मरीजों को पर्याप्त उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं।

हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे के साथ मां सर्वेश्वरी मंदिर का द्वितीय वार्षिकोत्सव सम्पन्न

अलीगढ़ । मां सर्वेश्वरी मंदिर के द्वितीय वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर द्वितीय दिवस अखंड रामायण पाठ संपन्न होने पर हवन यज्ञ एवं भण्डारे का आयोजन किया गया ।समाजसेवी भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक के अनुसार एशियन पब्लिक स्कूल वाली गली,न्यू. राजेंद्र नगर अलीगढ़ पर स्थित मां सर्वेश्वरी मंदिर का द्वितीय वार्षिकोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस अवसर पर द्वितीय दिन अखंड रामायण पाठ संपन्न होने के बाद हवन यज्ञ मे मुख्य आयोजक एडवोकेट संजीव कुमार वार्ष्णेय और उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी वार्ष्णेय ने पुर्नाहुति देकर समाज कल्याण की कामना की। हवन यज्ञ वैदिक रीति के साथ संपन्न करते हुए कहा कि सभी भक्तों को प्रतिदिन अपने अपने घरों पर हवन करना चाहिए इससे वातावरण में विचरण कर रहे अति सूक्ष्म विषैले कीटाणुओं का नाश होकर जगत में मानव का कल्याण होता है क्योंकि ग्रहस्थ व्यक्ति पूर्ण विधि विधान से यज्ञ को पूर्ण नहीं कर पाता है, इसके लिए विद्वान पंडितों द्वारा अखंड रामायण की संपूर्णता पर वैदिक रीति के साथ विधि विधान से मंत्रोच्चारण के मध्य यह हवन का कार्य पूर्ण किया जाता है। हवन एवम यज्ञ के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करने के उपरांत सभी भक्तों एवम बंधु वांधवों ने भंडारा ग्रहण किया।इस अवसर पर संजीव वार्ष्णेय, मीनाक्षी वार्ष्णेय, दीपक वार्ष्णेय, नेहा वार्ष्णेय, मुनील वार्ष्णेय, रुपाली वार्ष्णेय, भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक,निर्भय गुप्ता , बृजराज वार्ष्णेय, दिनेश गुप्ता, पंकज वार्ष्णेय, खेमेंद्र गुप्ता, आभा वार्ष्णेय, विशाल वार्ष्णेय, भव्य वार्ष्णेय, राकेश वार्ष्णेय, बुलबुल वार्ष्णेय, ज्योति वार्ष्णेय, अंकित गुप्ता, नूपुर वार्ष्णेय और अनन्य वार्ष्णेय आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन

अलीगढ़रूगुरुवार को 8 यूपी बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल अजय लूंबा के निर्देश पर नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ नशा मुक्ति अंत. र्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।रैली में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स,विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने"नशा मुक्त भारत"और "ल छव जव क्तनहे" जैसे नारों के माध्यम से समाज में नशे के दुष्परिणामों पर जागरूकता फैला. ई।रैली को रवाना करते समय कर्नल अजय लूबा ने संबोधित करते हुए कहा कि नशा समाज और युवा वर्ग को खोखला कर रहा है,अतःइसे रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने नशा छोड़ने में मदद करने वाले सरकारी हेल्पलाइन नंबर और पुनर्वास केंद्रों की भी जानकारी कैडेट्स को प्रदान की।मीडिया ओआइसी मेजर अरुण कुमार सिंह ने इस अवसर पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए इंटरनेट के जरिए मिलने वाली नशीली दवाओं और ऑनलाइन तस्करी से चेताते हुए कैडेट्स को नशे से दूर रहने और आमजन,खास कर युवा पीढ़ी को जागरूक करने हेतु प्रेरित किया।रैली के अंत में सभी ने नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ ली।. रैली में एनसीसी कैडेट्स के साथ–साथ एनसीसी अफसर कैप्टन नजफ अली,सूब. `दार वीरेंद्र सिंह,हवलदार अनूप कुमार आदि उपस्थित रहे।रैली में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

01 जुलाई से आरम्भ स्कूल चलो अभियान से परिषदीय विद्यालयों में बढ़ेगा नामांकन

अलीगढ़ (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह द्वारा बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए 1 जुलाई 2025 से ष्स्कूल चलो अभियानष् के दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत व्यापक स्तर पर नामांकन अभियान चलाया जाएगा। विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकगणों को लक्ष्य के अनुरूप नामांकन वृद्धि के लिए निर्देशित किया गया है।बीएसए ने यह भी बताया है कि वर्ष 2024–25 में कुल 2,20,000 बच्चों के सापेक्ष वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025–26 में अभी तक 1,94,870 बच्चों का नामांकन हो चुका है, जबकि नामांकन की समयसीमा 30 सितम्बर तक है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि नामांकन प्रक्रिया अभी प्रगति पर है और शेष तीन महीनों में पिछली वर्ष की तुलना में अधिक नामांकन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 160 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्रों की संख्या 20 से कम है, जिन्हें निकटवर्ती विद्यालयों में समायोजित करने की योजना पर भी कार्य प्रगति पर है, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग होने के साथ विद्यालयों में छात्र संख्या में प्रगति होगी और बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी। उन्होंने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील, यूनिफॉर्म, बैग, जूतेमोजे, पाठ्य पुस्. तकें, गुणवत्तापरक शिक्षा, छात्रवृत्ति की सुविधाओं और कायाकल्प योजना में विद्यालयों सौन्दर्यीकरण और शैक्षिक वातावरण में वृद्धि के चलते अभिभावकों का रुझान परिषदीय विद्यालयों की ओर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब परिषदीय विद्यालय किसी कॉन्वेंट या निजी

विद्यालयों से कम नहीं है। शैक्षिक गतिविधियों के साथ ही समर कैंप जैसे नवाचार ने अभिभावकों व बच्चों का रूझान परिषदीय विद्यालयों की ओर बढ़ाया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया है कि जिले में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा समर्पित प्रयास शिक्षा की रोशनी को हर घर तक पहुँचाने की दिशा में प्रभावी सिद्ध हो रहा है।

नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन

अलीगढ़, 26 जून कृ 8 यूपी बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल अजय लूंबा के निर्देश पर नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज अलीगढ़ में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स, विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने ष्नशा मुक्त भारतष् और ष्ैल छव जव क्तनहेष् जैसे नारों के माध्यम से समाज में नशे के दुष्परिणामों पर जागरूकता फैलाई।रैली को रवाना करते समय कर्नल अजय लूबा ने संबोधित करते हुए कहा कि नशा समाज और युवा वर्ग को खोखला कर रहा है, अतः इसे रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने नशा छोड़ने मैं मदद करने वाले सरकारी हेल्पलाइन नंबर और पुनर्वास केंद्रों की भी जानकारी कैडेट्स को प्रदान की। मीडिया ओआइसी मेजर अरुण कुमार सिंह ने इस अवसर पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए इंटरनेट के जरिए मिलने वाली नशीली दवाओं और ऑनलाइन तस्करी से चेताते हुए कैडेट्स को नशे से दूर रहने और आमजन, खास कर युवा पीढ़ी को जागरूक करने हेतु प्रेरित किया। रैली के अंत में सभी ने नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ ली। रैली में एनसीसी कैडेट्स के साथ–साथ एनसीसी अफसर कैप्टन नजफ अली,सूबेदार वीरेंद्र सिंह,हवलदार अनूप कुमार आदि उपस्थित रहे। रैली में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

मण्डलीय समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त ने दिए स्पष्ट निर्देश

अलीगढ़ कमिश्नरी सभागार में मण्डलायुक्त श्रीमती संगीता सिंह की अध्यक्षता में मण्डलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस जनपदों की विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था, राजस्व संग्रह और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में चारों जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।विकास कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुखमण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। विशेष रूप से जे.पी. नारायण सर्वोदय विद्यालयों के निर्माण में देरी पर उन्होंने यूपी सिडको के प्रति नारा. जगी प्रकट करते हुए कार्यों में तेजी लाने और लेट–लतीफी पर शासन को पत्र भे. जने के निर्देश दिए। जिलों की गिरती रैं. कंग पर चिंताबैठक में मई माह की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में मण्डल की पिछड़ती स्थिति पर भी चर्चा हुई। अलीगढ़ 58वें, एटा 67वें, कासगंज 70वें और हाथरस 27वें पायदान पर रहा। इस पर नाराजगी जताते हुए मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे टीम भावना से कार्य करते हुए सुधार के प्रयासों को तेज करें। उन्होंने कहा कि हाथरस ने जहाँ सुधार किया है, अलीगढ़ में मामूली तो वहीं एटा और कासगंज की रैंकिंग में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है, जोकि खेदजनक है।कानून व्यवस्था पर विशेष जोरमण्डलायुक्त ने पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था के प्रति सतर्क रहते हुए अपराध, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा एवं माफिया विरोधी कार्यवाही में और अधिक प्रभावशीलता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा आरंभ होने वाली है। सड़कों की मरम्मत कर ली जाए। मो.

हर्रम के जलूस में ताजिया निकलते हैं जिनकी ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए विद्युत तारों को दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने त्योहारों के दौरान यातायात प्रबंधन, विद्युत व्यवस्था, सफाई, शुद्व पेयजल आप. ूर्ति, जल निकासी, संचारी रोग नियंत्रण और ब्लैक स्पॉट को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।रा. जस्व और जनसेवा योजनाओं की समीक्षा राजस्व वसूली, लंबित वादों के निस्तारण और जनसुनवाई की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। फैमिली आईडी पोर्टल पर लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों की विसंगति पर विशेष ध्यान देने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। मंडलायुक्त ने रासायनिक उर्वरकों, खाद बीज, कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही मिलावट एवं कालाबाजारी, घटतौली पर विशेष निगाह रखने के निर्देश दिए।परिवहन एवं अधोसंरचनानई सड़कों के निर्माण में अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस की प्रगति धीमी रही, जिस पर नाराजगी जताई गई। कांवड़ यात्रा से पूर्व सभी प्रमुख मार्गों एवं गड्ढा–मुक्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए।पर्यावरण संरक्षण एवं पौधरोपणवन विभाग द्वारा मण्डल में 1.10 करोड़ से अधिक पौधरोपण की योजना प्रस्तुत की गई। डीएफओ नवीन प्रकाश ने बताया कि सहजन जैसे पोषक पौधे जीरो पॉवर्टी व पीएमध्सीएम आवास लाभार्थियों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। मण्डलायुक्त ने इसे व्यापक स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए।स्वरा. `जगार योजनाओं में प्रगति की आवश्यकतासीएम युवा योजना व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा संवेदनशीलता के साथ ऋण स्वीकृ ति पर बल दिया गया। सभी एलडीएम को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत आवेदनों पर शत–प्रतिशत ऋण वितरण सुनिश्चित करें।आईजीआरएस प्रणाली में लापरवाही पर नाराजगीमण्डलायुक्त ने जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा औपचारिकता में रिपोर्ट भेजी जा रही है। 182 में से 121 शिकायतकर्ताओं द्वारा असंतोष व्यक्त किया जाना चिंताजनक है। उन्होंने नगर निगम, खाद्य एवं रसद तथा चिकित्सा विभागों की बार–बार आ रही शिकायतों पर विशेष ध्यान देने को कहा।नदियों के पुनरोद्धार पर बलमण्डल की विलुप्त हो रही नदियों के पुनरोद्धार के निर्देश देते हुए आयुक्त ने संबंधित विभागों को कार्ययोजना तैयार कर अमल करने को कहा।जनहित में सतर्कता और संवेदनशीलता जरूरीबैठक के समापन पर मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे समर्पण भाव और संवेदनशीलता के साथ शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारें तथा जनविश्वास अर्जित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।इस अवसर पर डीएम अलीगढ़ संजीव रंजन, डीएम एटा प्रेम रंजन, डीएम हाथरस राहुल पाण्डेय, डीएम कासगंज मेधा रूपम, समस्त सीडीओ समेत मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में 06 कीटनाशी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त

अलीगढ़ जिला कृषि अधिकारी एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने जिले में कृषि रक्षा रसायनों की गुणवत्ता एवं नियम संगत बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सभी कीटनाशी लाइसेंस धारकों को निर्देशित किया जाता है कि वह बिना ला. इसेंस के अनाधिकृत रूप से किसी प्रकार के कृषि रक्षा रसायनों का उत्पादन एवं बिक्री न करें। लाइसेंस धारक कीटनाशक बिक्रेताओं के पास निर्धारित प्रारूप पर स्टाक पंजिकाएं कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उपलब्ध रहें एवं उस पर नियमित रूप से स्टाक का विवरण अंकित किया जायें। कीटनाशी रसायनों की बिक्री किये जाने पर कृषकों को अनिवार्य रूप से कैश मेमो निर्गत किया जाये। नकली, अधोमानक एवं कालातीत रसायनों की बिक्री किसी भी दशा में नही की जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त निर्देशो का उल्लंघन करने पर आपके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिले में महत्वपूर्ण तथ्य के सम्बन्ध में गलत बयानी, स्वयं के अनुरोध लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने में असफल रहने एवं किसी दूसरे जुर्माने जिसके लिये 06 कीटनाशी लाइसेंसों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आरएसपी एग्रीटेक लि0 बस स्टैण्ड, प्रवीन टेडर्स जीटी रोड, ओम कृषि रक्षा केन्द्र ललित मार्केट बस स्टैण्ड, लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र भवीगढ़, श्याम कृ षि रक्षा केन्द्र खैर रोड एवं साइनवुड एग्रो लि0 सिधौंली के कीटनाशी लाइसेंस को निरस्त किया गया है पीपीओ श्री चौधरी ने सभी कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि अपने कीटनाशी प्रतिष्ठान में वर्ष 2024–2025 एवं 2025–26 में विक्रित समस्त कीटनाशकों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप जिसमें कीटनाशी प्राप्त करने की तिथि, विनिर्माण एवं पूर्तिकार का नाम जिससे प्राप्त किया, बैच संख्या, विनिर्माण एवं अवसान की तिथि, इनवायस डिटेल, पिछला शेष, प्राप्त किया, विक्रय, अवशेष,

बिल संख्या (नाम पता जिसे बेचा व वित. रित किया गया) का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके प्रतिष्ठान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा एवं अधिनियम में उल्लेखित सुसंगत धाराओं के अधीन आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मण्डलायुक्त ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेकर जनसमस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

अलीगढ़ मीडिया को यूं ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता समाचार पत्र हों, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया, यह समाज का आईना होते हैं। शासनप्रशासन द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ संगीता सिंह ने मण्डलीय समीक्षा बैठक में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित जनहित की खबरों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए मण्डलायुक्त ने प्रमुख समाचार पत्रों में प्रक. ाशित समाचार जख्मी सड़कों से राहगीर परेशान विजयगढ़, सासनी एवं अकराबाद मार्ग की दुर्दशा ,तीन माह पहले खोला गया नाला जस का तसरू स्कूल खुलने पर बढ़ेगी समस्या , नाले ओवरफ्लो, सीवर का पानी सड़कों पर , सेंटर प्वाइंट फुटपाथ पर कब्जाश्श , श्श्चार हजार खर्च कीजिए, 100 साल के व्यक्ति का भी जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगाश्श , श्शशिक्षा की बदहालीरू जिले में शिक्षकों के 2947 पद खालीश्श एवं श्शबरसात में रोडवेज बसों के यात्री झेलेंगे दिक्कतें, खिड़कियों के टूटे शीशों से आएगा पानीश्श जैसी खबरों का उल्लेख करते हुए कहा कि मीडिया द्वारा उजागर की गई जनसमस्याएं वास्तविकता को सामने लाती हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जब समाचार पत्रों में समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है, तो संबंधित विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। हर समस्या का प्रभावी और समयबद्ध समाधान अनिवार्य है। इस अवसर पर सहायक निदेशक सूचना, संदीप कुमार ने जनहित में प्रकाशित समाचारों का समयबद्ध संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों से आख्या प्राप्त कर उच्चाधिकारियों तक भेजने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्य जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है, परंतु कुछ अधिकारी बार–बार कहने पर भी समय से आख्या प्रेषित नहीं करते हैं। मण्डलायुक्त ने इस पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए मण्डलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार द्वारा भेजी गई समाचार कटिंग्स को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध, तथ्यपरक व सारगर्भित आख्या प्रेषित करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी।

02 जुलाई से 30 अक्टूबर तक पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृति में होंगे ऑनलाइन आवेदन

अलीगढ़ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनहरी लाल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 202526 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्व दशम (कक्षा 9–10) व दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा (1112) के छात्रछात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए 202526 की समय सारिणी का शासनादेश निर्गत करते हुए छात्रवृत्तभुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि उक्त के क्रम में जिले के पूर्वदशम् व दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा के अल्पसंख्यक समुदाय (स्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन) के छात्रछात्राएँ https://scholarship-up-gov.पद पर ऑनलाईन आवेदन करें एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप हार्डक. ापी सम्बन्धित शिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराएं और सम्बन्धित शिक्षण संस्थान मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के साथ समय सारिणी के अनुसार कार्य करना सु. निश्चित करें।उन्होंने निर्धारित समय सारिणी की जानकारी देते हुए बताया कि 02 जुलाई से 14 दिसंबर तक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मार्किंग की जाएगी। 02 जुलाई से 30 अक्टूबर तक पूर्वदशम् व दशमोत्तर छात्रवृत्ति में छात्रछात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे एवं 04 नवंबर तक हार्ड कॉपी वाछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा की जाएगी। 06 नवंबर तक शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र–छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र का विद्यालय द्वारा मिलान कर अप्राप्त छात्रों का डाटा निरस्त एवं पात्र छात्रछात्राओं का आवेदन ऑनला. ईन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाएगा। 07 नवंबर से 15 नवंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन किया जाएगा और 07 से 17 नवंबर तक एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी। 18 से 21 नवंबर तक त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों व संस्था के स्तर से सही कराया जाएगा। 18 से 26 नवंबर तक संस्था द्वारा संलग्र अभिलेखों का पुनः मिलान कर अग्रसारित किया जाएगा। 18 नवंबर से 24 दिसंबर तक जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक किया जाएगा और 23 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक शुद्ध डाटा लॉक किया जाएगा।उन्होंने बताया कि नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ. साथ निर्धारित समयावधि में कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि समय सारिणी में श्श्अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मार्किंग किया जानाश्श के अनुसार अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली (संशोधित),2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी लॉगिन में प्रदार्शित मान्यता प्राप्त समस्त निजी क्षेत्र के कक्षा 9–10 व कक्षा 1112 के ऐसे विद्यालय जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर पंजीकृ त (रजिस्टर्ड) है, की ऑनलाईन मार्किंग की कार्यवाही समय सारिणी में दी गयी समय–सीमा में की जानी है समय सारिणी में दी गयी समय–सीमा के अन्दर छात्रों द्वारा आवेदन पूर्ण किये जाने व शिक्षण संस्थान द्वारा उन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन अग्रसारित किये जाने के लिए शिक्षण संस्थान को निरंतर सूचित किया जाना है। सीएम–डैशबोर्ड पर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत की जाने वाली समीक्षा में शिक्षण संस्थान के स्तर पर कोई आवेदन अग्रसारण के लिए लम्बित न रहे, इस सम्बन्ध में शिक्षण संस्थान के स्तर से पात्र आवेदनों को समयान्तर्गत अग्रसारित व अपात्र आवेदनों को निरस्त किया जाना है।नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि व गत कक्षा का परीक्षाफल को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल का पूर्णाक एवं प्राप्तांक व उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा। शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रत्येक आवेदक छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि छात्र का आधार अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते से सीडेड व एनपीसीआई में मैप्ड हो। किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा और गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक व जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। उन्होंने उपरोक्त के क्रम में जिले में संचालित समस्त पूर्वदशम् व दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं प्रबन्धक व प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि शासनादेशों में निहित प्रावधानों व नवीन समय सारिणी में दिये निर्देशों का संज्ञान लेते हुए वर्ष 2025–26 में निर्गत समयसारिणी में दी गई समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुए उल्लिखित नियमावली में प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2025–26 में छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन कराना सुनिशिचत करें।

अतरौली के रामघाट कल्याण मार्ग पर जिरौली धूमसिंह पुलिस चौकी के पास एक कार ने बाइक सवार को रौंद दिया

अतरौली के रामघाट कल्याण मार्ग पर जिरौली धूमसिंह पुलिस चौकी के पास एक कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। इससे बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है।गांव बैजला निवासी वीरेंद्र यादव 53 वर्ष पुत्र शंकरलाल एक ईंट भट्टा पर मुनीम थे। 26 जून की सुबह वह किसी कार्य से गांव मलहपुर गए थे। करीब नौ बजे वह अपने गांव वापस लौट रहे थे। रास्ते में तेज गति से जा रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इसके बाद कार सड़क किनारे पड़े कूड़े ढेर में धंस गई। लोगों ने दौड़कर वीरेंद्र को उठाया और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिससे परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया । खबर लिखे जाने तक किसी भी पक्ष ने थाने में तहरीर नहीं दी थी।

खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत जिले में सघन निरीक्षण, शुद्धता के लिए लिया गया 7 नमूनों का संकलन

अलीगढ़ (जिले में आम जनमानस को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया गया। इस क्रम में गुरूवार 26 जून 2025 को विभिन्न स्थानों से कुल 7 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहीत किए गए। संग्रहीत नमूनेरूसिकन्दरपुर, माछुआ स्थित दीपक दुग्ध संग्रह केंद्र से मिश्रित दूध का नमूना।सुदेशपुर में शहमत की दुकान से पनीर एवं मिश्रित दूध का एक और नमूना।शमशाद मार्केट, अनुपशहर रोड स्थित इम्तियाज की दुकान से फुल क्रीम मिल्क व गाय के दूध का नमूना।अनुपशहर रोड, बिंदल बीकानेर स्वीट्स से मिल्क केक व खोया का नमूनाउन्होंने बताया कि इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।सतत अभियान से जागरूकता और शुद्धता को बढ़ावाखाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे न केवल खाद्य कारोबारियों में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ रहा है। विभाग की यह निगरानी आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी।

सूचना
विज्ञापन एवं विज्ञप्ति के लिए सम्पर्क करें
कार्यालयः सरोज नगर गली न. 5, क्वार्सी
बाईपास रोड, अलीगढ़
हैल्पलाइन न.
8218049162,9870916612

उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला – कि अतिक्रमित भूमि पर रहने की वजह से किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता

उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला – कि अतिक्रमित भूमि पर रहने की वजह से किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता– भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को दोहराता है । वोटिंग का अधिकार संविधान की ओर से दिया गया है और इसका आधार जमीन का टुकड़ा नहीं हो सकता। न यह अधिकार इतना कमजोर है कि इसे किसी सरकारी फरमान से छीना जा सके।आदेश को चुनौतीरू उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारी, जंगल या किसी और जमीन पर अतिक्रमण करके रहने वालों को पंचायत चुनावों में मतदान करने या इलेक्शन लड़ने से वंचित किया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस पर साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मताधिकार सुरक्षित है और न्यायपालिका या सरकार कोई भी इसे वापस नहीं ले सकता। खतरनाक मिसालरू राज्य सरकार का यह आदेश अगर लागू हो जाता, तो एक खतरनाक मिसाल बन सकता था। देश के कई हिस्सों में आज भी लाखों लोग ऐसी जमीनों पर रह रहे हैं, जिनका स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, खासतौर पर शहरों के बीच बसी झुग्गियों, गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में। देश में वैसे भी जमीन से जुड़े मुकदमे बरसों तक चलने के लिए बदनाम हैं। कई मामलों में पीढ़ियां बदल गई और फैसला नहीं आया। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि इन्हें अतिक्रमणकारी बताकर इनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाए।हर अंदेशा दूर हुआरू लोकतंत्र में मताधिकार केवल चुनावी प्रक्रिया का एक अंग नहीं है। इसी से भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। संविधान ने देश के लोगों को यह अधिकार दिया है जब अनुच्छेद 326 के ड्राफ्ट आर्टिकल को शामिल किया जा रहा था, तब भी इस पर आपत्ति उठाई गई थी। एक सदस्य ने वयस्क मताधिकार का विरोध करते हुए अंदेशा जताया था कि अगर मतदाता जागरूक और शिक्षित न हुआ, तो संसदीय लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि वक्त ने इस अंदेशे को हवा में उड़ा दिया।मजबूत भरोसा हर नागरिक, जो निर्धारित आयु पूरी कर चुका हो और कुछ विशेष आधारों पर अयोग्य न हो, उसे मतदाता बनने का अधिकार है। शुरुआत में यह आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन के जरिये घटाकर 18 वर्ष किया गया। इसका मतलब कि देश का अपने लोगों पर यकीन और पक्का हुआ। जमीन से जुड़े विवाद को लेकर इस यकीन को तोड़ा नहीं जा सकता। हां, अतिक्रमण बड़ी समस्या है, पर उससे निपटने का तरीका वह नहीं, जो उत्तराखंड सरकार ने खोजा।

पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोल दी है कि पहलगाम आतंकी हमले में उसका हाथ नहीं था। अब तो इस बात के सबूत हैं कि सीमा पार इस हमले की साजिश ही नहीं रची गई, आतंकवादी भी वहां से आए थे और उन्हें पाकिस्तानी इस्टैब्लशमेंट का पूरा सपोर्ट था। इस खुलासे से पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पक्ष मजबूत हुआ है।आतंकियों के साथ पाकरू राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पाकिस्तान से आए लश्कर–ए–तैयबा के आतंकियों को पनाह दी थी। इनमें से एक आतंकी की पहचान हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान के रूप में हुई है, जो पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो रह चुका है। माना जा रहा है कि सेना ने मूसा को इस आतंकी मिशन के लिए ही लश्कर को दिया था। इससे एक बार फिर यह साबित होता है कि आतंकवाद पाकिस्तानी सेना की रणनीति का एक हिस्सा है और वह आतंकियों के साथ मिलकर काम करती है।कार्रवाई सही साबित हुईरू भारत का शुरू से कहना रहा है कि पहलगाम में पाकिस्तान शामिल है। उसके सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर यह घिनौनी वारदात हुई। यह खुलासा भारत के उन कदमों को सही ठहराता है, जो उसने पहलगाम के बाद उठाए थे – सीमा पार मौजूद आतंकी ढांचों को ध्वस्त करना और सिंधु जल समझौते का निलंबन।दबाव बनाए भारतरू टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली एजेंसी ॰।ज्थ् ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि इतना बड़ा आतंकी हमला आर्थिक मदद के बिना संभव नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को फिर से ॰।ज्थ् की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भारत अपनी बात मजबूती से रख सकता है। साथ ही, इससे पाकिस्तान पर लश्कर प्रमुख हाफिज सईद समेत उन आतंकियों पर कार्रवाई करने का भी दबाव बनाया जा सकता है, जिसे उसने अपने यहां छिपा रखा है।चौतरफा घेरने का मौकारू संसद पर हमला हो, मुंबई अटैक या फिर पठानकोट – हर बार पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आई और इसके बावजूद उसने अपना टेरर अजेंडा नहीं छोड़ा। ऐसे में यह उम्मीद नहीं कर सकते कि पहलगाम मामले में वह सच को सहजता से स्वीकार कर लेगा या अपनी आदत बदल देगा। हां, इस मौके का इस्तेमाल उसे घेरने और अमेरिका जैसे देशों की आंखें खोलने के लिए कर सकते हैं, जिन्हें अब भी पाकिस्तान पर भरोसा है।

ट्रंप से अब और सावधान हो जाए भारत, इजरायल–ईरान संघर्ष में अमेरिका की एंट्री चिंताजनक

दिव्य कुमार सोती। कुछ दिनों के भीषण युद्ध के बाद इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष विराम हो गया। कहना मुश्किल है कि यह संघर्ष विराम कितने समय तक टिकेगा? ईरान पर हमला बोलते समय इजरायल ने यह कहा था कि उसका उद्देश्य ईरानी परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना है। उसे कुछ आरंभिक सफलता भी हासिल हुई। उसके अचानक हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु विज्ञानी मारे गए। शुरुआती सफलता के बीच इजरायल ने कहना शुरू कर दिया कि हमले के पीछे उसके उद्देश्य बड़े हैं और एक उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन का भी है। ईरान की सत्ता उन कट्टर मजहबी नेताओं के कब्जे में है, जो हमास–हिजबुल्ला का साथ देते हैं। इजरायल के समर्थन में अमेरिका के कई ताकतवर नवरूढ़िवादी सांसदों कीआवाज भी उठने लगी। शुरुआत में अमेरिका इस लड़ाई में कूदने से हिचक रहा था, पर ईरान की जवाबी कार्रवाई से घिरे इजरायल की मदद के लिए आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी वायु सेना को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के आदेश देने ही पड़े। इसके बावजूद ईरानी परमाणु कार्यक्रम के पूरी तरह ध्वस्त होने को लेकर संदेह है। वैसे भी ईरान की मिसाइल क्षमता आशा से कहीं अधिक निकली। युद्ध लंबा खिंचने पर इजराइल में कहीं अधिक बर्बादी हो सकती थी। इसी कारण ट्रंप ने आनन–फानन युद्ध विराम का एलान भी कर दिया और वह भी अपने व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति के बिना, क्योंकि न तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो पाया और न ही वहां सत्ता परिवर्तन के कोई आसार दिख रहे। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि इजरायल और ट्रंप के मागा (मेक अमेरिकी ग्रेट अगेन) खेमे ने यह योजना सदा के लिए छोड़ दी है। सही मौका देखकर इसे फिर से क्रियान्वित करने का प्रयास होगा।वैसे तो अमेरिका को 'फिर से महान बनाने के अभियान' में लगा ट्रंप प्रशासन ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए किसी जमीनी युद्ध में नहीं उलझना चाहता, परंतु उसके इरादों को देखते हुए भारत को सतर्क होना होगा। भारत को सामरिक दृष्टिकोण से भी इस युद्ध के निहितार्थ समझने की आवश्यकता है। इजरायल–ईरान युद्ध के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप की ओर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की आवभगत का एक गहरा अर्थ है। जब मुनीर व्हाइट हाउस में थे, लगभग उसी समय अमेरिकी मदद से सत्तासीन बांग्लादेश की भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मिल रहे थे। दरअसल ट्रंप की मागा योजना के अंतर्गत अमेरिका का नए सिरे से जो उद्योगीकरण प्रस्तावित है, वह बिना चीन और रूस के पर कतरे और भारत को तंग किए बिना संभव नहीं है। इस योजना को सिरे चढ़ाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि भूमंडलीकरण के नाम पर अमेरिका ने ही अधिक मुनाफा कमाने के फेर में अपनी कंपनियों को चीन, वियतनाम जैसे देशों में स्थापित कराया। अब जब तक इन देशों में अमेरिकी कंपनियों के लिए उत्पादन के मोर्चे पर चुनौतियां नहीं दिखतीं, तब तक उनकी स्वदेश वापसी मुश्किल है। फिर भी अपनी योजना को लेकर अमेरिकी नवरूढ़िवादियों और ट्रंप के कथित युद्धविरोधी मागा खेमे में एक राय है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो तरीके चुने गए हैं।पहला तरीका है ट्रेड और टैरिफ नीति के जरिये रूस, चीन के साथ–साथ भारत का भी आर्थिक संकट बढ़ाना। दूसरा तरीका है कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तियों का अपने हित में इस्तेमाल करना। ट्रंप के चीनी वस्तुओं पर लगाए गए भारी टैरिफ के चलते चीन का अमेरिका को निर्यात काफी घटा है। यदि यह सिलसिला लंबे समय तक चला और चीन ने अपने निर्यात के लिए नए बाजार नहीं तलाशे तो वहां बड़ा औद्योगिक और सामाजिक संकट खड़ा हो सकता है।

भारत चीन के विरुद्ध एक तरह से अमेरिका का सामरिक साझेदार है, लेकिन ट्रंप मात्र इतने से संतुष्ट नहीं। उन्हें भारत के रूप में एक लोकतांत्रिक मित्र राष्ट्र नहीं, बल्कि उनके हिसाब से चलने वाला देश चाहिए। भारत के अमेरिका के बताए रास्ते पर चलने से साफ इन्कार करने के बाद अब यह अमेरिका के एजेंडे में नहीं दिखता कि उसकी मदद से भारत चीन जैसी आर्थिक शक्ति बनकर खड़ा हो। यह अच्छा हुआ कि भारत ने साफ कर दिया कि उसे अमेरिका से व्यापार समझौते की जल्दी नहीं।ट्रंप ने हाल में यह भी कहा था कि भारत एक बड़ा देश है और वह अपने मसले खुद देख लेगा। ध्यान रहे एक अमेरिकी सीनटेर रूसी तेल खरीदने के चलते भारत पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की वकालत कर चुके हैं। पाकिस्तान को शह देते ट्रंप भी भारत–पाकिस्तान सीजफायर के मुद्दे को भी जब तब व्यापार से जोड़ते रहते हैं। इसके पीछे उनका भारत के लिए यही संदेश है कि अगर टैरिफ जैसे मुद्दों पर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे पाकिस्तान के मोर्चे पर और दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। यदि बांग्लादेश में भी अमेरिका लगातार इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहा है तो भारत को परेशान करने के लिए ही। इन परिस्थितियों में रूसी विदेश मंत्री द्वारा प्रस्तावित रूस, चीन और भारत का त्रिकोण अब प्रासंगिक लगता है। चीन भी अब इसे लेकर सजग हो रहा है। भारत और चीन के रिश्तों में बर्फ पिघलती देखी जा सकती है। हाल में शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद आए चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में उल्लेख हुआ कि दोनों देश एक–दूसरे के प्रतिद्वंद्वी न होकर साझेदार हैं।जहां अमेरिकी टैरिफ के चलते चीन को एक बड़े बाजार की आवश्यकता है, वहीं भारत को त्वरित औद्योगिक विकास के लिए सस्ते कलपुर्जों की। दोनों देश एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। इसके बावजूद भारत को अपने सुरक्षा हितों के मामले में चीन को लेकर निरंतर सजग रहते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर पूर्व में चीन से बार–बार धोखा मिल चुका है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि चीन के साथ आर्थिक साझेदारी भारत के औद्योगिक विकास में सहायक हो और वह चीन पर निर्भरता का कारण न बने।

उच्च शिक्षा में कुछ अच्छा होता हुआ, शिक्षा संस्थानों पर भी ध्यान देना चाहिए

प्रणय कुमार। ईरान–इजरायल युद्ध के बीच शिक्षा क्षेत्र में भारत की एक उपलब्धि दबकर सी रह गई। क्यूएस (क्वाक्वेरेली साइमंड्स) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग–2026 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस वर्ष इसमें 106 देशों के कुल 1,501 शिक्षा संस्थानों को स्थान मिला, जिनमें 112 संस्थान पहली बार सम्मिलित हुए हैं। भारत के 54 संस्थानों को इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला, जो अब तक का रिकार्ड है। यह संख्या भारत को न केवल जर्मनी (48) और जापान (47) जैसे देशों से आगे ले जाती है, बल्कि इसे अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला देश भी बना देती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में भारत के केवल 11 संस्थान इस सूची में थे। यानी पिछले एक दशक में भारत ने लगभग पांच गुना वृद्धि दर्ज की है। इस वृद्धि में न केवल कई आइआइटी, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसे पारंपरिक एवं सरकारी संस्थानों–विश्वविद्यालयों ने योगदान दिया है, बल्कि कई निजी विश्वविद्यालयों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आठ भारतीय शिक्षा संस्थान पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं। यह भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ती भागीदारी का एक संकेत भी है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह वक्तव्य प्रासंगिक प्रतीत होता है, 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए शानदार खबर लेकर आई है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के लाभ के लिए शोध और नवाचार के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग उच्च शिक्षा की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और व्यापक रूप से संदर्भित रैंकिंग्स में से एक मानी जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन नौ संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, फैकल्टी–छात्र अनुपात, छात्र अनुपात, रोजगार परिणाम, अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क जैसे मानक शामिल हैं। उच्च शिक्षा में हुए हालिया सुधारों के पीछे कई महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की संस्तुतियों का व्यवस्थित क्रियान्वयन, शोध, अनुसंधान और नवाचार को निरंतर प्रोत्साहन तथा वैश्विक साझेदारियों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में गंभीर पहल की गई है। साथ ही हर स्तर पर तकनीकी दक्षता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा और उद्योग जगत के बीच की खाई पाटने, प्रवेश, फैकल्टी और विषय चयन की प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाने, विश्वविद्यालय परिसरों में विविधता और समावेशन की भावना को प्रोत्साहित करने और रोजगारोन्मुखी शिक्षा को सुदृढ़ करने जैसे कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं।शिक्षा के मोर्चे पर हो रहे व्यापक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत के आठ संस्थान प्रति फैकल्टी उद्धरण श्रेणी में विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हो चुके हैं। इस मानदंड पर भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी प्रकार नियोक्ता प्रतिष्ठा के मापदंड पर हमारे पांच विश्वविद्यालय वैश्विक शीर्ष 100 में स्थान पाने में सफल हुए हैं, जो उद्योग जगत में भारतीय स्नातकों के प्रति बढ़ते भरोसे का संकेत है।शैक्षणिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी आइआइटी, दिल्ली, बंबई और मद्रास जैसे संस्थानों ने अपनी फैकल्टी और वैश्विक शैक्षणिक साझेदारियों के चलते उच्च रेटिंग अर्जित की है। हालांकि इसी वर्ष जोड़े गए अंतरराष्ट्रीय छात्र विविधता जैसे संकेतकों में भारतीय विश्वविद्यालयों–संस्थानों को अपेक्षित रैंक नहीं मिली, जिसका समग्र रैंकिंग पर भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा पर और अधिक ध्यान देना होगा और इसकी कोशिश करनी होगी कि अन्य शिक्षा संस्थानों और विशेष रूप से राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे।क्यूएस या अन्य किसी भी वैश्विक रेटिंग एजेंसी को भी यह समझना होगा कि देश विशेष की परिस्थितियां भिन्न–भिन्न होती हैं। भारत जैसे देश की तुलना पश्चिमी देशों से नहीं हो सकती। भारत में इतनी विविधता है कि हमारे विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थान विविधता के उत्सव–स्थल हैं। निःसंदेह यह उपलब्धि प्रेरणास्पद है, परंतु हमें यह भी स्वीकारना होगा कि यह सफलता अभी मुख्यतः आइआइटी, कतिपय केंद्रीय विश्वविद्यालयों और चुनिंदा संस्थानों तक ही सीमित है। देश के अधिकांश विश्वविद्यालय अभी भी सीमित फंडिंग, कमतर शोध उत्पादन, सुयोग्य अध्यापकों की कमी, अधुनातन प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता, नवाचार के प्रति उदासीनता, अल्प अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं साझेदारी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वस्तुतः क्यूएस या किसी भी रैंकिंग्स को हमें लक्ष्य नहीं, दर्पण की तरह देखना चाहिए, जो हमें आत्मनिरीक्षण का भी संदेश देता है। वास्तविक उत्कृष्टता तो रैंकिंग्स से परे जाकर भारत के स्व को विस्मृत किए बिना शिक्षा का वैश्विक प्रतिमान गढ़ने एवं माडल खड़ा करने में है।

आपातकाल के सबक, लोकतंत्र को किया था शर्मसार

सत्ता और पद के मोह में इंदिरा गांधी की ओर से देश पर आपातकाल थोपने, विरोधियों के खिलाफ दमनचक्र चलाने और नौकरशाही को अपने हिसाब से काम करने के लिए विवश करने के घोर अलोकतांत्रिक फैसले के 50 वर्ष पूरे होने पर देश में विभिन्न आयोजन हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपातकाल के काले दिनों को याद किया। आज अनेक ऐसे नेता सक्रिय हैं, जिन्होंने 50 साल पहले आपातकाल के उत्पीड़न का सामना किया था। यह आश्चर्यजनक है कि आज कांग्रेस को आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सत्ता एवं कांग्रेस की राज्य सरकारों के दमनकारी रवैये का स्मरण किया जाना सहन नहीं हो रहा है। आपातकाल को लेकर जो कुछ कहा गया, उसका जवाब देते हुए कांग्रेस ने यह समझाया कि मोदी का शासन अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की मानें तो आज लोकतंत्र पर पांच गुना अधिक हमले हो रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी के आपातकाल पर उनके ऐसे ही विचार तब थे, जब वह कांग्रेस में नहीं थे? इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अपने निर्वाचन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रतिकूल फैसले और पीएम पद छोड़ने से बचने के लिए ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपकर भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार किया था। आपातकाल की सजा उन्हें 1977 के आम चुनाव में भोगनी पड़ी। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता में आई जनता पार्टी का शासन अधिक नहीं चला और इंदिरा गांधी 1980 में फिर से सत्ता में आ गईं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपातकाल को भुला दिया जाए।आपातकाल में इंदिरा गांधी ने मनमाने तरीके से शासन करने के अलावा परिवारवाद को भी आगे बढ़ाया। दमनचक्र चलाने और न्यायपालिका पर दबाव बनाने में उनके बेटे संजय गांधी की विशेष भूमिका थी। वह तो संविधान बदलने का इरादा

रखते थे। यह विडंबना ही है कि जिन नेताओं ने आपातकाल का डटकर विरोध किया, उनके वंशज और उनकी ओर से गठित कई दल आज कांग्रेस के साथ हैं। इस पर हैरानी नहीं कि इनमें से अधिकांश गांधी परिवार की तरह परिवारवाद की राजनीति को न केवल आगे बढ़ा रहे, बल्कि उसे सही भी ठहरा रहे हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि अपने विचित्र रवैये के कारण ही कांग्रेस उत्तर भारत में खास तौर पर कमजोर हो रही है। अपने पराभव के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए उसका कमजोर होना शुभ संकेत नहीं। वंशवादी गांधी परिवार पर आश्रित कांग्रेस शायद ही अपनी रीति–नीति सुधारे, पर उन प्रवृत्तियों से सभी को सावधान रहना चाहिए, जिनका परिचय आपातकाल में इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों ने दिया था। सभी को यह भी ध्यान रहे तो अच्छा कि अभी भारत को एक आदर्श लोकतांत्रिक देश बनना शेष है।